

बिग इश्यू

विश्वविद्यालयों की हालत खराब, रूस में भी प्रदेश को केवल 329 करोड़ रुपए ही स्वीकृत

विश्वविद्यालयों को नहीं मिल रहा यूजीसी से शोध अनुदान, रिसर्च प्रपोजल तक अटके

विनोद मित्तल | जयपुर

यूजीसी से 12वीं में मंजूर ग्रांट भी पूरी नहीं उठा पाए (राशि करोड़ में)

राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों की हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि न तो शोध के लिए यूजीसी से अनुदान मिल पा रहा है और ना ही सरकार से नए कोर्स स्वीकृत हो रहे हैं। विश्वविद्यालयों में एक-तिहाई पद खाली होने से शिक्षा स्तर गिरता जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी केवल बैठकें कर अनुदान जुटाने के लिए विश्वविद्यालयों को ही प्रयास करने की नसीहत दे रही हैं, लेकिन विभाग के स्तर पर कोई पहल नहीं हो रही।

हालात यह हैं कि प्रदेश के सबसे बड़े आर्यु को दो साल से यूजीसी से कोई रिसर्च अनुदान नहीं मिला है। यूनिवर्सिटी पोर्टेणियल फॉर एक्सीलेंस योजना के तहत यूजीसी से आर्यु को रिसर्च के लिए 50 करोड़ का अनुदान मिलना था। इसमें से दो साल पहले 25 करोड़ रुपए तो मिल गए, लेकिन 25 करोड़ रुपए आज तक बकाया चल रहे हैं। नॉन नेट शोधार्थियों को 8 हजार रुपए प्रतिमाह मिलने थे। दो साल से बजट नहीं आने से करीब 100 शोधार्थियों को भी यह पैसा नहीं मिल पाया। इसी बजट से रिसर्च के लिए प्रपोजल तैयार होते हैं। लेकिन बजट के अभाव में प्रपोजल अटक गए। प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों की भी कमोबेश यही हालत है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग (रूसा) से मिलने वाले अनुदान की राशि भी बहुत कम है। राजस्थान अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है। रूसा से केवल 329 करोड़ रु ही प्रदेश को मिल पाए हैं, जबकि केरल सहित कई राज्यों को एक हजार करोड़ से अधिक का अनुदान मिला है। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 200 से 250 विद्यार्थी ही पढ़ाई कर रहे हैं। वहां केंद्र सरकार ने करीब 100 करोड़ रुपए का अनुदान दे दिया।



एक साल में भी मंत्री नहीं सुधार पाईं हालात

यूजीसी से मिलने वाले अनुदान के अलावा प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग (रूसा) से भी ग्रांट मिलती है। यह ग्रांट नेक से थोड़ा प्राप्त होने के बाद ही दी जाती है। प्रदेश में पूर्व उच्च शिक्षामंत्री कालीचरण सराफ के समय भी सरकारी विश्वविद्यालय इस अनुदान को तरसते रहे। सराफ का विभाग पिछले साल दिसंबर में बदल गया। उनके स्थान पर उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी किरण माहेश्वरी ने संभाली। लेकिन हालात नहीं सुधरे और कमोबेश अब तक अनुदान के मामले में पहले जैसे ही हालात चल रहे हैं। माहेश्वरी को अगले महीने उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालते एक साल पूरा हो जाएगा।

निजी विवि के नए कोर्स अटकाए

विभागीय अव्यवस्था का खामियाजा सरकारी ही नहीं निजी विश्वविद्यालयों को भी भुगतना पड़ रहा है। निजी यूनिवर्सिटी को भी नए कोर्स की मान्यता नहीं मिल पा रही है। विश्वविद्यालयों एक्ट में शेड्यूल-2 के तहत शामिल कोर्स के अलावा कोर्स चलाने के लिए हर विश्वविद्यालयों को सरकार की मंजूरी की जरूरत होती है। उच्च शिक्षा विभाग में कई विश्वविद्यालयों ने कोर्स की मंजूरी के लिए फाइल भेजी थी। नया सत्र शुरू हो गया और उसको भी पांच महीने से अधिक बीत गया, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिल सकी है।

रूसा को लेकर केवल कर ली कुलपतियों की बैठक

उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने 6 नवंबर को विश्वविद्यालयों की बैठक ली। इसमें उन्होंने निर्देश दिया था कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त रूसा अनुदान राशि का कम से कम 75 प्रतिशत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें।

कमी नजर आती है तो विश्वविद्यालय करेंगे सुधार : माहेश्वरी

अनुदान देने से पहले यूजीसी की टीम पहले विश्वविद्यालयों का दौरा करती है। इसके बाद यूजीसी के मापदंडों पर खरा उतरने के बाद ही नियमानुसार उन्हें ग्रांट स्वीकृत होती है। टीम को कोई कमी नजर आती है तो विश्वविद्यालय स्तर पर ही उसको दूर किया जाता है।

- किरण माहेश्वरी, उच्च शिक्षा मंत्री

बकाया ग्रांट जल्दी ही मिल जाएगी। इसके लिए 27 से 29 नवंबर तक यूजीसी की टीम राजस्थान विश्वविद्यालय का दौरा करेगी। यह राशि लेप्स नहीं हुई है। हमने पहली किस्त का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवा दिया है।

- प्रो. एके नागावत, कोर्डिनेटर, राजस्थान यूनिवर्सिटी

राजस्थान विश्वविद्यालय को अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता तो इसका फायदा न केवल विद्यार्थियों बल्कि पूरे प्रदेश को मिलता। ग्रांट से यहां आधारभूत सुविधाएं विकसित होती। लेकिन सरकार की नीतियों के कारण यह विवि खुद का खर्चा निकालने को संघर्षरत है।

- विनोद शर्मा, महासचिव, रूटा

